राज्य में तकनीकी विकास के महानिदेशालय का कोई कार्यालय नहीं है ।

(ख) चूंकि तकनीकी विकास के महानिदेशालय के कार्य प्रमुख रूप से सलाह देने और विकास से सम्बन्धित हैं जिसमें संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं अतः क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

6095. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'हिन्दुस्तान' (हिन्दी) दिनांक 7 मार्च, 1973 में प्रकाशित दिल्ली के कार्यकारी पार्षद श्री ओ० पी० बहल के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमेंट की दिल्ली में जितनी मांग है उसमें आधा भी गत माह नहीं आया;

(ख) क्या इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई को सुनिश्चत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). निम्नलिखित कारणों से सीमेन्ट के उत्पादन में गिरावट आ जाने के कारण इन दिनों सीमेन्ट की कमी हो रही है :—

(क) 17 अगस्त, 1972 से 29 अगस्त, 1972 तक श्रमिकों की आम हड़ताल ।

(ख) हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा की गई बिजली की कटौती ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में मशीनों के खराब हो जाने तथा अशान्त स्थिति जिसके कारण यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

इन कारणों के फलस्वरूप सीमेन्ट के उत्पादन में हुई अनुमानित कमी करीब 4 लाख मी० टन प्रतिमास है । जहां तक दिल्ली क्षेत्र का सम्बन्ध है 1965 से लेकर दिल्ली को भेजी जाने वाली सीमेन्ट की मात्रा में निरन्तर वृद्धि होती रही है किन्तु मांग में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है । दिल्ली की सम्भरण स्थिति पर उपरि-लिखित कारणों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । जब कभी भी कमी की सूचना मिलती है, रेल विभाग के परामर्श से रेल द्वारा शीघ्रता से सीमेन्ट पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं । दिल्ली की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 13 मार्च, 1973 को 10,000 मी० टन अतिरिक्त सीमेन्ट भेजा गया था जो अब पहुंच गया है । समान वितरण का सुनिश्चय करने के लिए

दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 12 जुलाई, 1972 को एक आदेश भी जारी किया है जिसके द्वारा वह सीमेन्ट के प्रत्येक स्टाकिस्ट कीस्वास्तविक बिक्री पर नियन्त्रण रखता है ।

Scheme for development of Industries in Himachal Pradesh

6096. SHRI PRATAP SINGH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Himachal Government have submitted any scheme for development of small industries and medium industries in the State during 1973-74;

(b) if so, the outlines of the scheme and the nature of incentives proposed to be offered thereunder; and

(c) Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): (a) to (c). The annual plan proposals of Himachal Pradesh containing schemes for development of small, large and medium industries for 1973-74 were discussed in the Planning Commission. The schemes in the small scale sector include assistance under the State Aid to Industries Act and grant of loans by other State Financing Institutions such as the State's Small Industries Development Corporation, Industrial Cooperatives and Industrial Estates etc. The schemes under large and medium industries include modernisation and expansion of Nahan Foundry, taking up of new projects by the Himachal Pradesh, Mining and Industrial Development Corporation, establishment of a Cement factory, Granulated Fertilizer factory, projects for spindle units, a Woollen factory and a Brewery etc.

The incentives for promotion of smalll scale industries include liberalised credit under State Aid to Industries Act, loans at concessional rates of interest by the term lending institutions. Similar incentives are not given to large scale or medium units. In addition 10 per cent Central subsidy on capital investment by industrial units in selected backward districts of the State.

Following outlays in respect of large and medium industries and village and Small Industries have been approved by the Planning Commission for the year 1973-74:—

(Rs. in lakhs)

Large and Medium Industries	Village and Small Industries
95	61

Setting up of Public Sector Industries in Himachal Pradesh

6097. SHRI PRATAP SINGH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme for setting up some factories in the Public Sector in Himachal Pradesh during the year 1973-74; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b). The Cement Corporation of India have a proposal to set up a cement plant at Paonta (Himachal Pradesh) with a capacity of 2 lakhs tonnes per annum